



- केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, द्वीप समूह के एक दिवसीय दौरे पर कल श्री विजयपुरम पहुंचे।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे।
- कामकाजी अभिभावकों को सहयोग प्रदान करने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से फादर्स होम केंच स्थापित किया गया है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए न्यायालयों को सुलभ बनाने के विभिन्न उपाय किए गए हैं।



केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, द्वीप समूह के एक दिवसीय दौरे पर कल श्री विजयपुरम पहुंचे। यहां पहुंचने के तुरन्त बाद उन्होंने उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी. के. जोशी के साथ मुलाकात की। राज निवास में उपराज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को बिजली और शहरी विकास क्षेत्र में अंडमान और निकोबार प्रशासन की विभिन्न मेगा परियोजनाओं और द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से संचालित पर्यटन, आतिथ्य और बुनियादी ढांचे की पहलों से अवगत कराया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने एक समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड तथा पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने डॉलीगंज में एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड के बीस मेगावाट के आठ एम डब्ल्यू एच आर-सोलह मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली संयंत्र स्थल का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने संयंत्र स्थल पर उपस्थित एन.एल.सी. अधिकारियों से सौर संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता एवं वितरण के बारे में जानकारी ली।

दौरे के दौरान दक्षिण अंडमान के उपायुक्त अर्जुन शर्मा, सचिव श्रम एवं रोजगार, डॉ. अनिल अग्रवाल, विद्युत विभाग के निदेशक डॉ. प्रशांत कुमार, एन एल सी इंडिया लिमिटेड और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद, विद्युत मंत्री ने मार्च दो हजार तेरह में चालू किए गए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा गराचर्मा में पांच मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र का दौरा किया। यह संयंत्र एन टी पी सी और अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा द्वीपों को हरा-भरा बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती बढ़ाने की पहली पहल है, जिससे द्वीपों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। एन टी पी सी के सी जी एम अनिल श्रीवास्तव ने केन्द्रीय मंत्री को सौर ऊर्जा संयंत्र के कामकाज के बारे में भी जानकारी दी।

<><><><><><><><>

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति खन्ना को ग्यारह नवम्बर से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे देश के इक्यावनवें मुख्य न्यायाधीश होंगे और तेरह नवम्बर दो हजार पच्चीस को सेवा निवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अट्ठारह जनवरी दो हजार उन्नीस को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया था। इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न संविधान पीठों में काम किया और अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए।

<><><><><><><><>

कामकाजी अभिभावकों को सहयोग प्रदान करने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से विभाग के कार्यालय भवन परिसर में फादर्स होम केंच स्थापित किया गया है। गैर सरकारी संगठन पंख के सहयोग से स्थापित इस केंच का उद्घाटन मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने किया। इस अवसर पर आयुक्त व सचिव सहकारिता, नन्दिनी पालीवाल ने अपने संक्षिप्त संबोधन में सहकारिता विभाग के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार जिन संस्थानों में पचास या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां केंच की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने इसी तरह की सेवाएं अन्य विभागों में भी शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष सचिव सहकारिता व सहकारी समितियों के पंजीयक नन्दिनी महाराज ने कहा कि इस केंच के माध्यम से छः वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को पोषण सहित शैक्षणिक पर्यावरण भी उपलब्ध हो जाएगा और इससे कामकाजी अभिभावकों को बच्चों की देखभाल के लिए एक सुनहरा विकल्प मिलेगा। कार्यक्रम में चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानन्द सरस्वती और पंख की अध्यक्षा कोमल आनन्द ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कोमल आनन्द ने बताया

कि इस फादर्स होम क्वेच में बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया गया है और मामूली शुल्क की अदायगी कर कामकाजी अभिभावक बिना मानसिक तनाव के अपने बच्चों को देखभाल के लिए इसमें छोड़ सकते हैं तथा कार्यालय अवधि और भोजनावकाश के दौरान वे अपने बच्चों से भी मिल सकते हैं।



भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड ने कहा है कि पिछले पचहत्तर वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय वास्तविक अर्थों में लोक न्यायालय के रूप में सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने लोक न्यायालय के रूप में सेवा करने का यह उदाहरण विश्व में कहीं और नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए न्यायालयों को सुलभ बनाने के विभिन्न उपाय किए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पचहत्तर वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने बोलने और सुनने में अक्षम वकीलों को सांकेतिक भाषा जानने वाले दुभाषिये उपलब्ध कराने की शुरुआत की है।



देश भर के साथ अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में भी कल से पशुधन जनगणना का कार्य आरंभ किया गया है। प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाले इस जनगणना के माध्यम से पशुधन की संख्या का पता लगाया जाएगा, जो पशुधन के क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाओं को तैयार करने और इसे मूर्त रूप देने में सहयोग प्रदान करेगा, जिससे देश की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान मिल सके। पशुधन जनगणना के जरिए घरेलू पशुओं और पॉल्ट्री मुर्गियों की वास्तविक संख्या का पता लगेगा। द्वीपसमूह के तीनों ज़िलों के अलावा सैन्य प्रतिष्ठानों, अर्धचिकित्सा बलों और राज्य पुलिस संस्थानों में भी यह कार्य किया जाएगा। इस पशुधन जनगणना में आवारा पशुओं की लिंग अनुसार भी जनगणना होगी। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में पशुपालन और पशुचिकित्सा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो साठ से अधिक गणनाकारों और अधिकारियों के सहयोग से ज़िले के साढ़े पांच सौ से अधिक गांव में इस कार्य को सम्पन्न करेंगे। उम्मीद की जाती है अगले वर्ष फरवरी में पशुधन जनगणना की अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। द्वीपसमूह के सभी पशुधन मालिकों से इस कार्य में सहयोग देने का अनुरोध किया गया है।



युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार दो हजार चौबीस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए यह पुरस्कार हर साल प्रदान किये जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को लगातार उत्कृष्ट खेल के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) इस क्षेत्र में आजीवन योगदान

के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने वाले कोचों को दिया जाता है। पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ी, कोच और संस्था चौदह नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल **dbtyas-sports.gov.in** पर आवेदन जमा कर सकेंगे।

<><><><><><><>